कालीपद चक्रवर्ती और अन्य

बनाम

पलानी बालादेवी और अन्य

(न्याधीपति मुखर्जी एवं चंद्रशेखर अय्यर और गुलाम हसन जेजे.)

हिन्दू कानून-धार्मिक दान-शेबैती अधिकार विधवा के द्वारा उत्तराधिकार- विधवा के अधिकार की प्रकृति और सीमा-विधवा द्वारा अंतरण अंतरिती के विरूद्ध प्रत्यावर्तक (रिवर्जनर) द्वरा दावा-परिसीमा अनुच्छेद लागू है प्रारंभिक बिंदू-विधवा के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जा, चाहे प्रत्यावर्तक के प्रतिकूल हो, परिसीमा अधिनियम (IX ऑफ 1908) 124, 141।

हालांकि शेबैती अधिकार में एक तत्व है जिसमें संपत्ति की कानूनी विशेषताएं हैं शेबैती एक विशिष्टि चरित्र की संपत्ति है और यह विधि के अंतर्गत अचल संपत्ति की श्रेणी में नहीं आती जैसा की कानून में है शेबैती अधिकार वंशानुगत पद है जैसा की अनुच्छेद 124 सीमा अधिनियम के अंतर्गत अभिव्यक्त है प्रत्यावर्तक के द्वारा मुकदमा शेबैती अधिकार की वापस प्राप्त करने जिनके लिए एक हिन्दू विधवा अपने पति की मृत्यु पर संपत्ति प्राप्त करने में सफल हुयी थी ने उसे अलग कर दिया अनुच्छेद 124 परिसीमा अधिनियम द्वारा शासित होता हैं न कि 141 के द्वारा। अंतरिती का कब्जा प्रत्यावर्तक के प्रतिकूल हो जाता है और सीमा अवधि प्रत्यावर्तक के खिलाफ तभी चलने लगती है जब उसके लिए उत्तराधिकार खुला रहता है। जैसा की वह विधवा के अधिकार के तहत दावा नहीं कर सकता बल्कि अंतिम पुरूष धारक के रूप में कर सकता है।

ज्ञान संबंद्ध बनाम वेलू {(1900) 27 आई.ए. 69} में स्पष्ट किया गया।

एक न्यासी के पद के बारे में जो कुछ भी कहा जा सकता हैं जिसमें कोई लाभकारी हित नहीं है शेबियतशीप में पद और संपत्ति दानों के तत्व को जोड़ती है

शेबिती का हित वंशानुगत है और संस्थापत से विरासत की पंक्ति का अनुसरण करता है जब उत्तराधिकारी एक महिला होती है तो उसे शेबैती के हित में विधवा की संपत्ति के रूप में जाना जाता है। सामान्यतया विधवा की संपत्ति पर दो सीमाएं होती है। पहली बात या सबसे पहले उसके अंतरण के अधिकार के प्रतिबंधित है और दूसरे स्थान पर बाद उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को नहीं मिलती बल्कि अंतिम पुरूष स्वामी को मिल जाती है दुसरा तत्व एक महिला शेबेत के उत्तराधिकारों के अधिकार के बारे में दूसरा तत्व मौजूद है जहॉ तक पहले के संबंध में बिल्कूल सत्य है कि अंतरण की शक्ति से एक महिला शेबेट पुरूष शेबेट के समान ही प्रतिबंधित है लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि शेबेती के अधिकार से जुडी कुछ सीमाएं व प्रतिबंध है जो इस तथ्य के बावजूद मौजूद है कि शेबेटशिप एक पुरूष एक महिला अधिकारी में निहित है या नहीं है।

पाइडिगैंटन वी रामादास {(1905) आई.एल. 28 मैड 197} और लीलाबती बनाम बिशन {(1907) 6 सी.एल.जे. 621} में टिप्पणी की।

यह नियम हिन्दू विधवा के खिलाफ प्रतिकुल कब्जा को प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारी के रूप नहीं माना जा सकता यह कोई विशेष नियम नहीं जो पूरी तरह से परिसीमा अधिनियम की अनुच्छेद 141 पर निर्भर करती है अनुच्छेद 141 परिसीमा अधिनियम और इसके संचालन मंे उन मामलों में सीमित जो उस अनुच्छेद के दायरे में आते है यह हिन्दू कानून के स्वीकृत सिद्धातों और सामान्य सिद्धांत के अनुसार है जैसा की प्रत्यावर्तकों का अधिकार विशेष उत्तराधिकार की प्रकृति में है और वे शीर्षक (स्वामित्व) का पता विधवा के माध्यम से या उससे नहीं लगाते है यह स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण होगा यदि वे विधवा की लापरवाही से अपने अधिकार खो देते है।

श्रीनाथ कुएर बनाम प्रोसून्ना कुमार {(1883) आई.एल.आर. 9 कैल. 934} रणछोडदास बनाम पार्वती {(1899) 26 आई.ए. 71} जग्गू बनाम उत्सव {(1929) 56 आई.ए. 267} अनुमोदित। कटामा नचियार बनाम शिवगंगा के राजा {(1925) 52 आई.ए 332} संदर्भित है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील 19/1952।

19 जून 1950 के निर्णय और आदेश से उच्च न्याालय कोलकाता (न्यायाधीपति दास एवं गुहा)। मूल डिक्री नं 48/1949 जो निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 दिसम्बर, 1948 से अधिनस्थ न्यायालय के कोर्ट नं. 3, 24 परगना के जज के द्वारा बाद शिर्षक नं. 53/1944 से उद्भुत अपील में।

एन.सी. चटर्जी (ए.के. दत्त उनके साथ) - अपीलार्थीगण की ओर से।

पंचानन घोष (राधाकांत भट्टाचार्य उनके साथ)- प्रत्यर्थी की ओर से।

16 जनवरी, 1953 को न्यायालय के निर्णय दिया गया।

न्यायामूर्ति मुखर्जी - यह अपील वादियों की ओर से है ओर खंडपीठ कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से फैसले ओर डिक्री के खिलाफ निर्देशित है। 19 जून 1950 को कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठ ने अधिनस्थ के न्यायालय 24 परगना के बाद शीर्षक नं. 53/1944 आदेश को अपील में पलटते हुये पारित किया हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए तथ्य सामग्री विवाद में नहीं है ओर पक्षों के बीच विवाद एक छोटे से बिंदु के आसपास केंद्रित है अर्थात् वादी का मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित है या नहीं है।

विचारण अदालत ने वादी के पक्ष में इस बिंदु का फैसला किया जबकि अपील में उच्च न्यायालय द्वारा विपरीत दृष्टिकोण रहा विाद का विषय एक निजी नवोदित व्यक्ति के संबंध में शेबैती अधिकार का एक तिहाई हिस्सा है।

ढोप ढोपी नामक गांव में स्थित दक्षिणेश्वर यहूदी के नाम से जानी जाने वाली एक मूर्ति को समर्पित जो पश्चिम बंगाल में 24-परगना जिले के भीतर देवता की प्रचीन मूर्ति है और इसके प्रतिष्ठित संस्थापक और पहले शेबत एक उधब चंद्र पंडित थे। यह विवादित नहीं है कि लगातार हस्तांतरणों से शेबत के अधिकार एक ईश्वर में निहित हो गए। चंद्र चक्रवर्ती जो इस मुकदमें के पक्षकारों के सामान्य पूर्वज थे। निम्नलिखित वंशावली तालिका उन कई व्यक्तियों के संबंधों को स्पष्ट करेगी जो वर्तमान मुकदमें में पक्षकार के रूप में खुद के और अपने आम लोगों के बीच भी है।

<u>वंशावली</u>

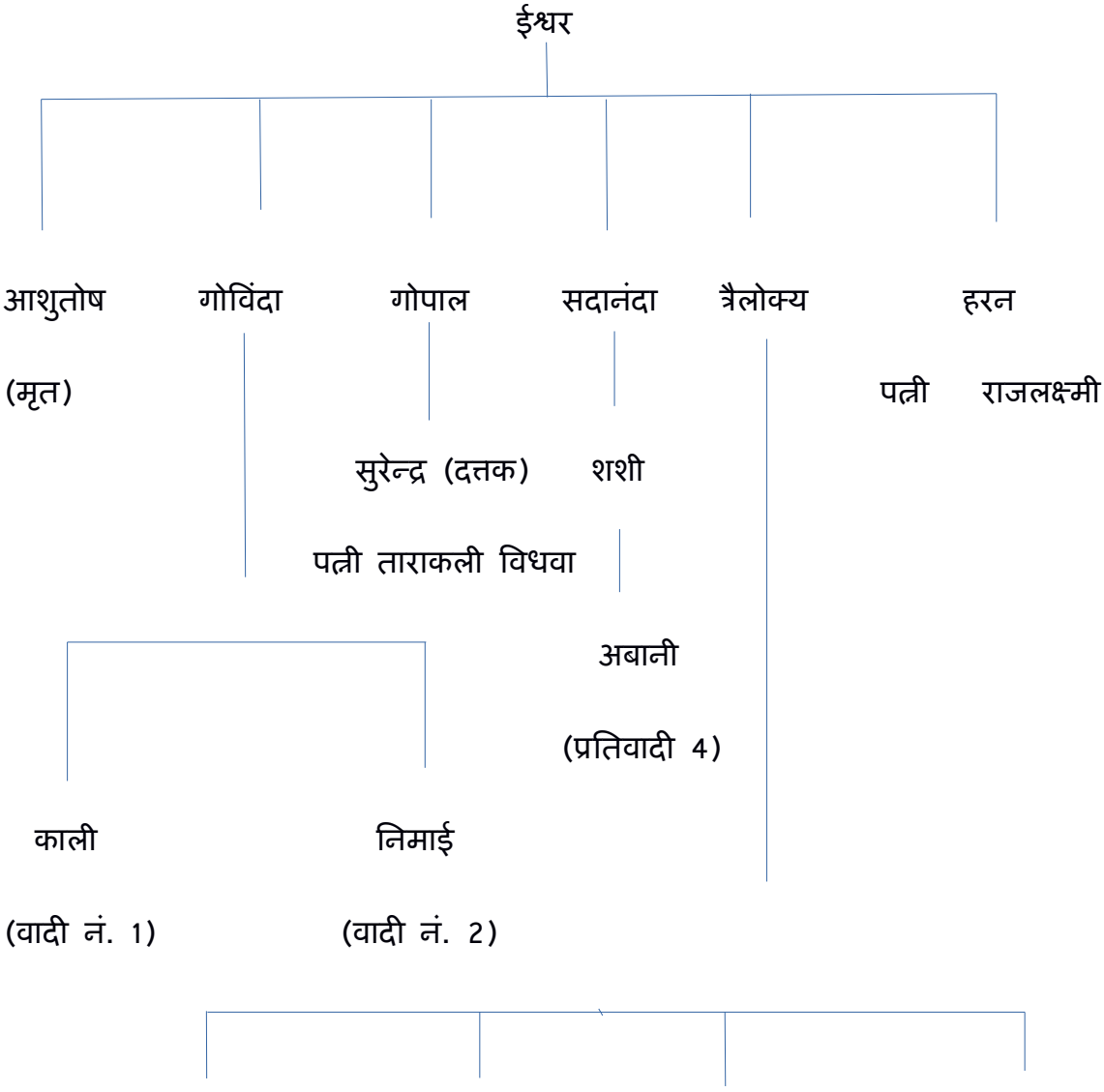

मोनी	सरत	सुरेन्द्र	नागेन्द्र
(मृत)	बिधु	(गोपाल के द्वारा गोद)	पलानी बाली
	(प्रति. 3)		(प्रति. 1)

ईश्वर की मृत्यु उनके उत्तराधिकारी के रूप में छह पुत्रों को छोड़कर हुई और वे थे आशुतोष, गोविंदा, गोपाल, सदानंद, त्रैलोक्य और हरन। इन छह बेटों ने जब अपने पिता की संपत्तियों का बंटवारा किया तो शेबैती अधिकार को भी बांट दिया, जो उन्हें छः बराबर हिस्सों में मिला था, और यह बंटवारा पारी या पूजा के रूप में जाना जाने वाली विधि द्वारा किया गया था जिसका अर्थ है कि प्रत्येक बेटों को हर महीने 5 दिनों के लिए देवता की पूजा करने का अधिकार आवंटित किया गया था और इन दिनों के दौरान उन्हें अकेले शेबैत के कार्यों का निर्वहन करना था और कार्यालय से जुड़ी परिलब्धियां प्राप्त करनी थीं। धीरे-धीरे परिवार में एक प्रथा विकसित हुई जिसके अनुसार इन पारी (बारी) को खरीदा और बेचा जा सकता था या अन्यथा शेबैत के परिवार के सदस्यों के बीच अलग-थलग कर दिया जा सकता था। गोविंदा जो वादी के पिता थे और जिन्हें अपने हिस्से में हर महीने 5 दिन का पाला मिलता था, ने शेबैती में अपनी हिस्सेदारी अपने एक भाई हरन को बेच दी, और इसका परिणाम यह हुआ कि हरन को हर महीने 10 दिन का पाला मिलता था या संपूर्ण शेबैती अधिकार में एक-तिहाई हिस्सा। हरन की बिना किसी समस्या के मृत्यु हो गई और वह जीवित रह गया उसकी विधवा राजलक्ष्मी हिंदू कानून के तहत उसकी एकमात्र उत्तराधिकारी थी और राजलक्ष्मी ने मृतक की अन्य संपत्तियों के साथ-साथ शेबैती का यह एक तिहाई हिस्सा भी अपने पास रखा। 17 जून 1920 को राजलक्ष्मी ने अपने शेबैती अधिकार का इजारा पट्टा दो

साल की अवधि के लिए सतीश चंद्र डे को दिया। 1 अप्रैल, 1921 को सतीश ने पारी (बारी) के संबंध में इस पट्टेदारी को राम राखल घोष नामक व्यक्ति को बेच दिया। उससे पहले, 6 अगस्त, 1920 को राम राखल ने खुद राजलक्ष्मी से उनके शेबैती अधिकार का पट्टा 5 साल की अवधि के लिए लिया था, यह पट्टा सतीश के पक्ष में पिछले पट्टे की समाप्ति पर शुरू होना था। राम राखल ने स्वीकार किया कि उसने शेबैत के कार्यालय पर कब्ज़ा कर लिया और 1 अप्रैल, 1921 से अपने अधिकारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। दिनांक 7 नवंबर, 1921 के एक हस्तांतरण विलेख द्वारा, राजलक्ष्मी ने राम राखल के पक्ष में अपनी शेबैती की पूरी बिक्री की और इस खरीद के बीस दिन बाद यानी 27 नवंबर 1921 को, राम राखल ने इस हित को त्रिलोक्य के दो बेटों को नागेंद्र और सुरेंद्र को बेच दिया। कुछ समय बाद सुरेंद्र की मृत्यु हो गई और 20 जून 1925 को उनकी विधवा ताराकली ने शेबैती अधिकार में अपने पति का हिस्सा अपने पति के भाई नागेंद्र को बेच दिया। इस प्रकार नागेंद्र को अपने पिता से जो कुछ विरासत में मिला था, उसके अलावा शेबैती अधिकार में एक तिहाई हिस्सा भी मिला, जो हर महीने 10 दिनों के पारी (बारी) द्वारा दर्शाया जाता था, जो पहले हरन के पास था। 22 दिसंबर, 1943 को राजलक्ष्मी की मृत्यु हो गई, और दो वादी जो गोविंदा के दो जीवित पुत्र हैं, ने मुकदमा दायर किया जिसमें से हरन के इस एक तिहाई शेबैती अधिकार के कब्जे की वसूली के लिए यह अपील इस आरोप पर उत्पन्न हुई कि वे राजलक्ष्मी की मृत्यु के समय हरन के अगले उत्तराधिकारी थे।

इस बीच नागेंद्र की मृत्यु हो गई थी और मुकदमे में पहली और मुख्य प्रतिवादी उनकी बेटी पलानी बाला है, जो नाबालिग है और उसका पति अभिभावक के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा प्रतिवादी रिसीवर है, जिसे 24-परगना के जिला न्यायाधीश के समक्ष लंबित संरक्षकता कार्यवाही में पलानी बाला की संपत्तियों का प्रभारी बनाया गया है। प्रतिवादी 3 और 4 ईश्वर के जीवित वंशज हैं जो शेबैती में शेष हित रखते हैं।

वादी का मामला संक्षेप में यह है कि शेबैती अधिकार का एक तिहाई हिस्सा, जो हरन के पास उसके जीवनकाल के दौरान था वह उसकी विधवा राजलक्ष्मी को हस्तांतरित कर दिया गया, एक हिन्दू विधवा के संबंध में जिसके पास केवल प्रतिबंधित अधिकार था। विधवा की मृत्यु पर, वादी में हित निहित था, जो राजलक्ष्मी की मृत्यु के समय हरण के निकटतम उत्तराधिकारी थे।

तदनुसार, उन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 को बेदखल करने के बाद, जैसा कि ऊपर कहा गया है, हर महीने 10 दिनों के पारी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए शेबैती अधिकार के इस एक तिहाई हिस्से पर कब्जा करने के लिए प्रार्थना की। विधवा की मृत्यु की तारीख से मध्यकालीन लाभ के लिए भी दावा किया गया था। दावे में मंदिर, उसकी सहायक भूमि और उस पर खड़ी संरचनाओं का विवरण दिया गया है, लेकिन इन संपत्तियों के संबंध में कब्जे के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई है। प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से मुकदमे का विरोध किया गया और मुख्य तर्क यह उठाया गया कि हरण की विधवा राजलक्ष्मी द्वारा उसके शेबैती अधिकार की बिक्री एक शून्य ट्रांज़ैक्शन थी जो हस्तांतरिती में कोई अधिकार नहीं बनाता, राम राखल और उनके बाद उनके प्रतिवादियों का कब्ज़ा जो प्रतिवादी नंबर 1 के पूर्ववर्ती थे, सभी शेबैतों के खिलाफ प्रतिकूल था, और प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से शेबैती अधिकार में इस तीसरे हिस्से के लिए एक अजेय शीर्षक हासिल कर लिया और वादी का मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित था। कई अन्य विवाद भी उठाए गए लेकिन वे हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

ट्रायल जज ने 22 दिसंबर, 1948 को अपने फैसले से प्रतिवादी की दलीलों को खारिज कर दिया और वादी को डिक्री दे दी। परिसीमा के प्रश्न पर, अधीनस्थ न्यायाधीश ने माना कि यद्यपि भारतीय परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 141 इस मामले पर लागू नहीं होता, फिर भी वादी का मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं था। इस दृष्टिकोण के

लिए दो कारण बताए गए हैं। सबसे पहले यह कहा गया है कि नागेंद्र ने केवल राजलक्ष्मी के जीवन हित को खरीदने का इरादा किया था; परिणामस्वरूप क्रेता के रूप में उसकी स्थिति हरन के प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारियों के हित में मान्यता प्राप्त थी। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि राजलक्ष्मी और नागेंद्र दोनों देवता के सह-शेबेट थे, इसलिए बाद वाले का कब्ज़ा पूर्व के प्रतिकूल नहीं हो सकता था क्योंकि वे कानून में सह-हिस्सेदार की स्थिति में थे और निष्कासन (बाहरी) जैसा कुछ भी आरोप या तर्क इस मामले में साबित नहीं हुआ था।

इस फैसले के खिलाफ, प्रतिवादी 1 और 2 ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की और अपील की सुनवाई दास और गुहा जे जे की खंडपीठ ने की। विद्वान न्यायाधीशों ने ट्रायल जज द्वारा निकाले गए अन्य सभी निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए परिसीमा के प्रश्न पर बाद में असहमति जताई। उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि इस मामले में लागू करने के लिए उचित अनुच्छेद सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 124 था, और चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 और उसके पूर्ववर्तियों ने वादी के प्रतिकूल शेबेट के वंशानुगत कार्यालय पर कब्जा कर लिया था। मुकदमा शुरू होने से 12 वर्ष से अधिक पहले, वादी का दावा परिसीमा द्वारा वर्जित था। इस दृष्टि से, ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलट दिया गया और वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया।

इस अपील में हमारे सामने एकमात्र बिंदु परिसीमा का है और इस बिंदु पर दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा हमारे सामने जो तर्क दिए गए हैं, वे वास्तव में हमारे विनिश्चय के लिए दो प्रश्न खड़े करते हैं। पहला यह है कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों पर वादी का मुकदमा परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 141 द्वारा शासित होता है? यदि अनुच्छेद 141 उपयुक्त अनुच्छेद है, तो यह विवादित नहीं है कि वादी का मुकदमा समय के भीतर है; लेकिन यदि अनुच्छेद 124 लागू है, तो दूसरा बिंदु जिस पर विचार करने की आवश्यकता होगी, वह यह है कि प्रतिवादी या उसके

पूर्ववर्तियों ने वादी के प्रतिकूल शेबैत के वंशानुगत कार्यालय पर कब कब्ज़ा कर लिया? क्या राजलक्ष्मी द्वारा हस्तांतरण की तिथि से ही उनका कब्ज़ा प्रतिकूल था या उनकी मृत्यु के बाद ही ऐसा हुआ था...?

यह प्रस्ताव अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी अजनबी के पक्ष में शेबैती का शेबैती अधिकार का हनन हिंदू कानून में बिल्कुल शून्य है और इसे किसी प्रथा के आधार पर भी मान्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए अधिकार से वंचित व्यक्ति अतिक्रमणकारी है और अंतरणकर्ता के विरुद्ध उसका कब्ज़ा शुरू से ही प्रतिकूल है। वादी अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री चटर्जी ने कानून की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया है। कानून के इस प्रस्ताव की सत्यता; उनका तर्क यह है कि प्रतिवादी नंबर 1 और उसके पूर्ववर्तियों द्वारा शेबैती अधिकार का कब्ज़ा हस्तांतरण की तारीख के बाद से राजलक्ष्मी के खिलाफ प्रतिकूल हो सकता है और इस तरह के कब्जे के बल पर उन्होंने वैधानिक अधिकार हासिल कर लिया होगा शेबैती हित के संबंध में उसके विरुद्ध शीर्षक; लेकिन वैधानिक अवधि से अधिक के लिए इस तरह का प्रतिकूल कब्ज़ा, भले ही विधवा को रोक सकता है, लेकिन प्रत्यावर्तकों को नहीं रोकेगा जो उससे या उसके माध्यम से अपना स्वामित्व प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह 1871 से ही भारत में परिसीमा कानून का अंतर्निहित सिद्धांत है और परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 141 स्पष्ट रूप से इसे मान्यता देता है और इसे प्रभावी बनाता है। श्री चटर्जी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भले ही अनुच्छेद 141 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है और अनुच्छेद 124 को उपयुक्त अनुच्छेद माना जाता है, वादी का मुकदमा समय के भीतर होगा जैसा कि प्रतिवादी या उसके पूर्ववर्तियों को होना चाहिए। यह माना जाता है कि शेबैत के कार्यालय पर वर्तमान वादी के प्रतिकूल कब्ज़ा तभी हुआ जब विधवा की मृत्यु हो गई, उससे पहले नहीं।

दूसरी ओर, श्री पंचानन घोष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कानून के सामान्य सिद्धांत जैसा कुछ भी नहीं है कि एक हिंदू विधवा के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे को उसके प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि, यह केवल एक विशेष नियम है जो पूरी तरह से सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 141 के विशेष प्रावधान पर निर्भर करता है और इसके संचालन में उन मामलों तक ही सीमित है जो उस अनुच्छेद के दायरे में आते हैं।श्री घोष का तर्क यह है कि अनुच्छेद 141 का इस मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है और परिणामस्वरूप विधवा के विरुद्ध प्रतिकूल कब्ज़ा रखने का कोई कारण नहीं है यदि इसे वैधानिक अवधि के लिए जारी रखा गया तो प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारियों पर भी रोक नहीं होगी। उनका कहना है, यह क़ानून की किताब में अनुच्छेद 141 को शामिल करने से पहले का कानून था और यही वह कानून है जो अब भी उन सभी मामलों को नियंत्रित करता है जो सीधे तौर पर उस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आते हैं। विद्वान वकील के अनुसार, अनुच्छेद 124 उचित अनुच्छेद है जो इसे नियंत्रित करता है। हस्तानांतणकर्ता का कब्जा और शेबैटी के हित की हस्तांतरित कब्जे को प्रतिकूल रूप से स्वीकार किया जा रहा है। स्थानांतरण की तिथि पर कार्यालय का धारक, यह अगले धारक के विरुद्ध भी प्रतिकूल होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या उसने अपना शीर्षक पिछले धारक से प्राप्त किया है या नहीं। मामले में आग्रह किया गया है कि शेबेट जैसे वंशानुगत कार्यालय की, शक्तियाँ मादा शेबेट की शक्तियां पुरूष शेबैट तुलना में किसी भी तरह से अधिक प्रतिबंधित नहीं हैं एक नर शेबेट के और उस दौरान ट्रस्ट की संपत्ति के रूप में एक महिला शेबेट की सत्ता पूरी तरह और प्रभावी रूप से उसी में रहती है जैसे कि एक पुरुष ट्रस्टी में, उसके बाद आने वाला पुरुष ट्रस्टी उस सिद्धांत के लाभ का दावा नहीं कर सकता जिस पर परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 141 आधारित है। उठाए गए बिंदु महत्वपूर्ण है इसमें संदेह नहीं है और सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है।

शुरुआत में ही इसका उल्लेख किया जा सकता है कि पुराने लिमिटेशन एक्ट (अधिनियम XXIV, 1859) में किसी हिंदू विधवा द्वारा अपने प्रतिबंधित अधिकार में रखी गई संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए पुनर्वित्तकर्ताओं द्वारा मुकदमों से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं था।अनुभागों में केवल अत्यंत सामान्य चरित्र के प्रावधान थे। अधिनियम की धारा 12 और 16, जिसके तहत अचल और चल संपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने के लिए मुकदमों की सीमा क्रमशः कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने के समय से 12 और 6 वर्ष थी।इस अधिनियम के पारित होने से पहले ही, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए एक मामले (गोलकमनी बनाम दिगम्बर 1852) में, पील, सी.जे. ने निम्नलिखित टिप्पणी की थीः

> ''कई वर्षों से यह विचार किया जाता रहा है कि विधवा पूरी तरह से संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, और यह भी स्थापित कानून है कि प्रतिकूल कब्ज़ा उसके बाद के उत्तराधिकारी को रोकता है, जो कि तब नहीं होता जब वह जीवन के लिए केवल किरायेदार होती, जैसा कि अंग्रेजी कानून से ज्ञात है' ।
>
> 1863 में कतामा नैचिएर बनाम शिवगुंगा के राजा (2) के मामले का फैसला प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा किया गया था और प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर तब से सवाल नहीं उठाया गया है, कि "जब एक मृत हिंदू की संपत्ति एक महिला उत्तराधिकारी में निहित, उसकी संपत्ति के संबंध में उसके खिलाफ निष्पक्ष रूप से और उचित रूप से प्राप्त की गई डिक्री प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारी पर धोखाधड़ी या मिलीभगत के बंधन के अभाव में होती है।" टर्नर एल.जे., जिन्होंने बोर्ड का निर्णय सुनाया, ने अपने निर्णय के दौरान कहाः

"कुछ समय के लिए पूरी संपत्ति पूरी तरह से कुछ उद्देश्यों के लिए, हालांकि कुछ मामलों में योग्य हित के लिए, उसमें निहित होगी; और उसकी मृत्यु तक यह सुनिश्चित नहीं किया जाएगा कि सफल होने का हकदार कौन होगा। वही सिद्धांत जो इस देश की अदालतों में विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले किरायेदार के संबंध में प्रचलित है, एक हिंदू विधवा के मामले में लागू होता प्रतीत होता है; और यह स्पष्ट है कि यह मानने में सबसे बड़ी असुविधा होगी कि उत्तराधिकारी विधवा के खिलाफ निष्पक्ष और उचित तरीके से प्राप्त डिक्री से बंधे हुए नहीं थे।

मामला पूरी तरह से इस आधार पर आगे बढ़ा कि यद्यपि कुछ उद्देश्यों के लिए विधवा को अपने पति की संपत्ति में केवल आंशिक हित होती है, अन्य उद्देश्यों के लिए पूरी संपत्ति उसमें निहित होती है, और उसकी हित कुछ हद तक किरायेदार के समान होती है अंग्रेजी कानून के तहत होता है। यदि मुकदमा विधवा के खिलाफ व्यक्तिगत दावे के संबंध में नहीं था, बल्कि उस संपत्ति के संबंध में था, जिसका कानून में वह पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करती है, तो निष्पक्ष और उचित रूप से प्राप्त डिक्री प्रत्यावर्ती हित (जुगुल किशोर बनाम जोतेन्द्रों प्ण्।ण् 66 रू73 से संबंधित) को बाध्य करेगी। इस मामले में प्रतिकूल कब्जे का कोई सवाल ही नहीं उठाया गया था, लेकिन 1859 के लिमिटेशन एक्ट के तहत कई मामलों को तय करने में इसमें दिए गए नियम पर भरोसा किया गया था, जहां यह सवाल उठा था कि क्या वैधानिक अवधि से अधिक के लिए प्रतिकूल कब्जा है। जो विधवा व उसके प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारियों पर भी रोक लगाता है। इस

बिंदु पर प्रमुख घोषणा नोबिन चंदर बनाम इस्सुर चंदर में पाई जाती है, जिस पर श्री घोष ने बहुत अधिक जोर दिया है। उस मामले में एक अतिचारी ने विधवा के खिलाफ संपत्ति पर कब्जा कर लिया और यह माना गया कि इस तरह का प्रतिकूल कब्जा उलटने वालों के खिलाफ भी प्रभावी था। ऐसा कहा गया कि कार्रवाई का कारण विधवा को उपार्जित किया गया और उसे उसके द्वारा या उसके प्रत्यावर्तक द्वारा एक दावा लाना होगा। निर्धारित बेदखली की तारीख से 12 वर्ष के भीतर लाना होगा। 1859 के परिसीमा अधिनियम की धारा 12 के अनुसार निर्णय को निश्चित रूप से परिसीमा के कानून के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है जैसा की परिसीमा उस समय थी। 1859 के अधिनियम में प्रत्यावर्तनकर्ताओं के संबंध में एक अलग नियम प्रदान नहीं किया गया था और अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए सभी मुकदमों को कार्रवाई के कारण की तारीख से 12 साल के भीतर लाया जाना था। यदि विधवा के विरुद्ध कोई अतिचार हुआ था, तो अतिचार का प्रारंभ मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण होगा और अतिचारी के विरुद्ध मुकदमा 12 वर्षों के भीतर लाना होगा, चाहे वह विधवा द्वारा लाया गया हो या प्रत्यावर्तनकर्ता द्वारा विद्वान न्यायाधीश इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे कि विधवा के जीवनकाल के दौरान प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारियों के लिए कब्जे के लिए मुकदमा दायर करना संभव नहीं था। हालाँकि, शिवगुंगा के मामले में प्रतिपादित "विधवा द्वारा संपत्ति का प्रतिनिधित्व" के सिद्धांत को लागू करके कठिनाई को समाप्त कर दिया गया था। "सर बार्न्स पीकॉक, सी.जे. ने इस प्रकार निर्धारित कियाः

"ऐसा कहा जाता है कि प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारी विधवा के जीवनकाल के दौरान कब्जे के लिए मुकदमा नहीं कर सकते थे, और इसलिए उन्हें उस समय विधवा के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल धारण से रोका नहीं जाना चाहिए जब वे मुकदमा नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हम विधवा को एक प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं और देखते हैं कि प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारी उसके पति की संपत्ति से संबंधित डिक्री से बंधे हैं जो उसके खिलाफ धोखाधड़ी या मिलीभगत के बिना प्राप्त की गई हैं, तो हमारी राय है कि वे भी उस सीमा से बंधे हैं जिसके द्वारा वह, धोखाधड़ी या मिलीभगत के बिना, वर्जित है।"

चूँकि किसी विधवा के विरुद्ध प्रतिकूल निर्णय को संपत्ति के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर प्रत्यावर्तक के लिए बाध्यकारी माना जाता था, उसके विरुद्ध प्रतिकूल कब्जे के मामले में भी इसी तरह का परिणाम माना जाता था ताकि प्रत्यावर्ती हित को समाप्त किया जा सके। इस सिद्धांत की प्रिवी काउंसिल ने औमिरटोलाल बनाम राजोनी कांट(1) में पुष्टि की थी और फैसला सुनाने वाले सर बार्न्स पीकॉक ने नोबिन चंदर बनाम इस्सुर चंदर में फैसले की स्पष्ट रूप से पुष्टि की थी। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि हालांकि इस मामले में प्रिवी काउंसिल का फैसला वर्ष 1875 में पारित किया गया था, लेकिन यह 1859 के पुराने लिमिटेशन एक्ट के तहत एक निर्णय था।

1871 में एक नया सीमा अधिनियम पारित किया गया जिसमें 1859 के पिछले अधिनियम को निरस्त कर दिया। इस अधिनियम का अनुच्छेद 142 (जो वर्तमान अधिनियम के अनुच्छेद 141 से मेल खाता है) स्पष्ट रूप से एक हिंदू महिला उत्तराधिकारी की मृत्यु पर अचल संपत्ति के कब्जे के हकदार एक हिंदू द्वारा मुकदमे के लिए 12 साल की सीमा अवधि निर्धारित करता है। चलने की सीमा उस समय से जब महिला उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई। इस प्रावधान को, आगे बढ़ाया गया ताकि एक

मुसलमान द्वारा किए गए मुकदमे को शामिल किया जा सके, 1877 के अधिनियम में और फिर वर्तमान अधिनियम के अनुच्छेद 141 में पुनः प्रस्तुत किया गया। हमें यह मानना सही लगता है कि यह मौजूदा कानून में विधायिका द्वारा जानबूझकर किया गया बदलाव था। अनुच्छेद 141 एक समान मुकदमे की बात करता है और इसका मतलब है कि यह अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए एक मुकदमा है जिसका प्रावधान पिछले अनुच्छेद में किया गया है। पिछला अनुच्छेद अंग्रेजी वकीलों के तकनीकी अर्थ में एक शेष व्यक्ति या एक प्रत्यावर्तक द्वारा एक मुकदमे से संबंधित है और यदि "प्रत्यावर्तनकर्ता" शब्द का उपयोग हिंदू या मुस्लिम महिला उत्तराधिकारी की संपत्ति के संदर्भ में किया जाता है, तो भ्रम न हो, विधायिका जानबूझकर शब्दों का प्रयोग किया गया ष्एक हिंदू या मुसलमान महिला उत्तराधिकारी की मृत्यु पर संपत्ति पर कब्ज़ा करने का हकदार है।ष् एक हिंदू महिला उत्तराधिकारी की संपत्ति, जैसा कि सर्वविदित है, अपने चरित्र में बेहद विसंगतिपूर्ण है; इसे या तो विरासत की संपत्ति या जीवन भर के लिए एक संपत्ति के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, हालांकि यह दोनों की प्रकृति का हिस्सा है। इस प्रावधान को शुरू करने में विधायिका का इरादा स्पष्ट रूप से परिसीमा के कानून को लागू करने के उद्देश्य से इन विसंगतियों को दूर करना था और इस उद्देश्य के लिए हिंदू विधवा की संपत्ति को जीवन भर के लिए किरायेदार की संपत्ति में पूरी तरह से शामिल कर लिया गया था'"श्रीनाथ कुर बनाम प्रोसुन्नो कुमार (1883 9 बंस. 934') में कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा और वुंद्रावंदास बनाम कर्सोंदास (1897) 21 बाम्बे 646 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में, हमारी राय में, यह दृष्टिकोण बिल्कुल सही था। बाद वाले मामले को रणछोडदास बनाम पार्वती (1899) 26 1.A-71 में प्रिवी काउंसिल द्वारा पुष्टि की गई। रणछोडदास के मामले में निर्णय को हमेशा से इस प्रस्ताव के लिए एक अधिकार के रूप में माना गया है कि जब एक सीमित संपत्ति रखने वाली हिंदू महिला को बेदखल किया जाता है, तो

परिसीमन का क़ानून उलटने वाले के खिलाफ चलना शुरू नहीं होता है; और ऐसे मामलों में प्रत्यावर्तक को महिला उत्तराधिकारी की मृत्यु से 12 साल के भीतर मुकदमा दायर करने का अधिकार है, जब संपत्ति वास्तविक रूप से कब्जे में आ जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रणछोडदास के मामले में न्यायिक समिति ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि उन चल संपत्तियों के संबंध में भी, जिन पर अनुच्छेद 141 लागू नहीं होता है, संपत्ति पर प्रत्यावर्तक का अधिकार विधवा की मृत्यु पर होता है, उससे पहले नहीं। कुछ मामलों.में राय व्यक्त की गई थी कि रणछोड़दास के मामले में लिया गया दृष्टिकोण वैथियालिंगा बनाम श्रीरंगथ (3) में न्यायिक समिति की बाद की घोषणा से काफी हद तक हिल गया था, और यह कि संपत्ति के प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जिस विधवा पर शिवगुंगा के मामले में नियम लागू था, उसे विधवा के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे के मामले में लागू किया जा सकता है। लेकिन इस बिंदु पर सभी संदेह जग्गो बनाम उत्सव (4) में प्रिवी काउंसिल के निर्णय से ही स्थापित हो गए थे और कानून को अब पूरी तरह से अच्छी तरह से तय माना जा सकता है, सिवाय इसके कि जहां डिक्री निष्पक्ष और उचित तरीके से प्राप्त की गई हो और एक सीमित मालिक के रूप में उसके द्वारा रखी गई संपत्ति के संबंध में हिंदू महिला उत्तराधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी और मिलीभगत के बिना, महिला उत्तराधिकारी या अतिचारी से किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ ऐसी संपत्ति की वसूली के लिए एक प्रत्यावर्तक द्वारा मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण जो उसके प्रति प्रतिकूल आचरण करता है वह केवल महिला उत्तराधिकारी की मृत्यु पर ही अर्जित होता है। यह सिद्धांत, जिसे इस देश में 1871 से ही परिसीमा के कानून में मान्यता दी गई है, हमें हिंदू कानून के स्वीकृत सिद्धांतों के काफी अनुरूप लगता है। प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारियों का अधिकार विशिष्ट उत्तराधिकारियों की प्रकृति में है, और चूंकि प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारियों को विधवा के माध्यम से या उससे अपना शीर्षक नहीं मिलता है, यह स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण होगा यदि वे अपने

अधिकारों को केवल इसलिए खो देते हैं क्योंकि विधवा ने संपत्ति का नुकसान उठाया है किसी अजनबी के प्रतिकूल कब्जे से नष्ट हो गया। इसलिए, ऐसे मामलों में लागू होने वाले सामान्य सिद्धांत के संबंध में श्री घोष द्वारा उठाए गए तर्क को सही नहीं माना जा सकता है।

अब मामले में उठाए गए विशिष्ट बिंदुओं पर आते हुए, पहली बात जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या वर्तमान मुकदमा अनुच्छेद 124 द्वारा शासित है या परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 141 से शासित है। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने बिल्कुल उचित रूप से माना है कि अनुच्छेद 141 के लाभ का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब महिला उत्तराधिकारी के पास योग्य संपत्ति हो, जिसकी मृत्यु के बाद वादी अंतिम पुरुष धारक के उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति का हकदार था। हालाँकि, विद्वान न्यायाधीशों के अनुसार, यह शर्त वर्तमान मामले में पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि विवाद का विषय शेबेटशिप का अधिकार था और ऐसा कहा जाता है कि मादा शेबेट के अधिकार किसी भी तरह से अधिक प्रतिबंधित या योग्य नहीं हैं। वह पुरुष शेबेट की तुलना में योग्य है, हालाँकि वह इस पद को अपने उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित नहीं कर सकती है। इस संबंध में पाइडिगेंटन बनाम रामा दास में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है, जिसके बाद लीलाबती बनाम बिशेन में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया था। दृष्टिकोण का यह तरीका हमें संदेह के लिए खुला प्रतीत होता है। एक ट्रस्टी के कार्यालय के बारे में जो कुछ भी कहा जा सकता है, जिसमें कोई लाभकारी हित नहीं होता है, एक शेबेटशिप, जैसा कि अब अच्छी तरह से स्थापित है, इसमें कार्यालय और संपत्ति दोनों तत्वों का संयोजन होता है। चूँकि शेबैती हित वंशानुगत है और संस्थापक से विरासत की रेखा का अनुसरण करता है, जाहिर है जब उत्तराधिकारी एक महिला है, तो उसे शेबैती हित में विधवा की संपत्ति के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर विधवा

की संपत्ति पर दो सीमाएं होती हैं। पहले स्थान पर उसके अन्तरण के अधिकार प्रतिबंधित हैं और दूसरे स्थान पर, उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को नहीं बल्कि अंतिम पुरुष मालिक के उत्तराधिकारियों को मिलती है। यह स्वीकार किया गया है कि मादा शेबेट के अधिकारों के उत्तराधिकार के मामले में दूसरा तत्व मौजूद है। जहां तक पहले का संबंध है, यह बिल्कुल सच है कि अलगाव की शक्तियों के संबंध में, मादा शेबेट को नर शेबेट की तरह ही प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि शेबैती अधिकार से जुड़ी और उसमें निहित कुछ सीमाएं और प्रतिबंध हैं जो कि इस तथ्य की परवाह किए बिना अस्तित्व में है कि शेबेटशिप पुरुष या महिला उत्तराधिकारी में निहित है

लेकिन यद्यपि हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई तर्क की इस पंक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हम विद्वान न्यायाधीशों से सहमत हैं कि इस मामले में लागू होने वाला उचित अनुच्छेद अनुच्छेद 124 है न कि अनुच्छेद 141। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि शेबैती अधिकार में एक तत्व है जिसके पास है। संपत्ति की कानूनी विशेषताएं; लेकिन शेबेटशिप एक अजीब और असामान्य चरित्र की संपत्ति है, और यह कहना मुश्किल है कि यह अचल संपत्ति की श्रेणी में आती है जैसा कि कानून में जाना जाता है। अनुच्छेद 141 स्पष्ट रूप से अचल संपत्ति को संदर्भित करता है न कि शब्द के सामान्य अर्थ में संपत्ति को। दूसरी ओर, यह बिल्कुल तय है कि शेबैती अधिकार एक वंशानुगत कार्यालय है और इस तरह यह सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 124 की स्पष्ट भाषा के अंतर्गत आता है। हमारा मानना है कि जब लिमिटेशन एक्ट में एक विशिष्ट लेख है जो किसी विशेष मामले को कवर करता है, तो किसी अन्य लेख को लागू करना उचित नहीं है, जिसका आवेदन संदेह से मुक्त नहीं है। इसलिए, हमारा मानना है कि अनुच्छेद 124 लागू करने के लिए उचित अनुच्छेद है, और अब सवाल

उठता है कि क्या वादी का मुकदमा इस अनुच्छेद के तहत परिसीमन से वर्जित है, जैसा कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने माना है?

अनुच्छेद 124 एक वंशानुगत कार्यालय के कब्जे के लिए एक मुकदमे से संबंधित है और ऐसे मुकदमे के लिए निर्धारित सीमा की अवधि उस तारीख से 12 वर्ष है जब प्रतिवादी कार्यालय पर प्रतिकूल कब्जा कर लेता है। वादी को विधायिका का इरादा स्पष्ट रूप से ऐसे कार्यालय के कब्जे के लिए मुकदमों को रोकने और एक निश्चित अवधि के बाद उस पर कब्जे के अधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से वंशानुगत कार्यालय को भूमि की तरह व्यवहार करना है। सवाल यह है कि प्रतिवादी या उसके पूर्ववर्ती ने वादी के प्रतिकूल, शेबैत के कार्यालय पर कब कब्ज़ा कर लिया? यह माना जाता है कि यह कब्ज़ा उस समय शेबैती की धारक राजलक्ष्मी के प्रतिकूल था; लेकिन श्री चटर्जी का तर्क यह है कि चूंकि वादी ने राजलक्ष्मी के माध्यम से या उससे दावा नहीं किया था, इसलिए प्रतिवादी को वादी के प्रतिकूल कार्यालय पर कब्जा करने वाला नहीं माना जा सकता है। वह इस संबंध में लिमिटेशन एक्ट की धारा 2 (8) में " वादी " की परिभाषा का हवाला देते हैं, जहां यह कहा गया है कि वादी में कोई भी व्यक्ति शामिल है जिससे या जिसके माध्यम से वादी को मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके उत्तर में, श्री घोष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एक ट्रस्टी की तरह एक शेबेट संपूर्ण ट्रस्ट संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और अगला ट्रस्टी, भले ही कार्यालय के पिछले धारक के माध्यम से या उससे सख्ती से दावा नहीं कर सकता है, उसे माना जाना चाहिए बाद के कृत्यों या चूक से बंधा हुआ; और इस विवाद के समर्थन में ज्ञानसंबंद बनाम वेलु में न्यायिक समिति के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है। हमें नहीं लगता कि यह विवाद सही है अनुच्छेद 124 वंशानुगत पद से संबंधित है और इसका मतलब यह है कि पद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास केवल इस कारण से जाता है कि वह पूर्व का उत्तराधिकारी है। विरासत के हिंदू कानून के तहत, जब एक महिला उत्तराधिकारी

हस्तक्षेप करती है, तो उसके जीवनकाल के दौरान संपत्ति में उसका सीमित हित होता है और उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार उसके उत्तराधिकारियों के लिए नहीं बल्कि अंतिम पुरुष धारक के उत्तराधिकारियों के लिए खुल जाता है। इस बात पर न तो विवाद हुआ है और न ही इस पर विवाद किया जा सकता है कि शेबैतशिप के उत्तराधिकार की आसानी में भी यही नियम लागू होता है। धारा 2 (8) के साथ सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 124 का शीर्षक देते हुए, यह निष्कर्ष अपरिवर्तनीय है कि अनुच्छेद 124 के तहत वादी के शीर्षक को पराजित करने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि प्रतिवादी ने वादी या किसी के प्रतिकूल कार्यालय पर कब्जा कर लिया है। मुकदमा शुरू होने से 12 वर्ष से पहले वादी ने अपना स्वामित्व प्राप्त किया हो। यह बिल्कुल वही है जो ज्ञानसंबंद बनाम वेलु में निर्धारित किया गया था। इस मामले में दो व्यक्तियों ने, जो एक धार्मिक बंदोबस्ती के वंशानुगत ट्रस्टी थे, प्रबंधन का अपना अधिकार बेच दिया और पूरी संपन्न संपत्ति प्रतिवादी अपीलकर्ता को हस्तांतरित कर दी। बिक्री अमान्य थी और क्रेता द्वारा लिया गया कब्ज़ा शुरू से ही विक्रेताओं के प्रतिकूल था। वादी वेलु वंशानुगत ट्रस्टियों में से एक का बेटा और उत्तराधिकारी था और लेन-देन की तारीख के 12 साल से अधिक समय बाद उसने दूसरे ट्रस्टी के उत्तराधिकारी के साथ कार्यालय पर कब्जे का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया था, जो प्रतिवादी के रूप में शामिल हुआ था। न्यायिक समिति द्वारा यह माना गया कि वादी के मुकदमे को रोक दिया गया था और कारण यह दिया गया है कि "प्रतिवादी वेलु केवल अपने पिता नटराज के उत्तराधिकारी के रूप में और उनसे और उनके माध्यम से हकदार हो सकते हैं, और परिणामस्वरूप उनके मुकदमे को अनुच्छेद 114 द्वारा रोक दिया गया था।" ऐसा लगता है कि फैसले के इस हिस्से को कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों और ऊपर उल्लिखित मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा भी नजरअंदाज कर दिया गया था। तथ्य यह है कि विरासत के सामान्य कानून के तहत वादी राजलक्ष्मी के पति के उत्तराधिकारी के रूप में आएंगे, यह

महत्वहीन है। इससे विधवा के माध्यम से और उससे मुकदमा करने का उनका अधिकार प्राप्त नहीं होगा, और इस मामले को देखते हुए वादी के मुकदमे को वर्जित नहीं माना जा सकता है। इसलिए, परिणाम यह है कि हम अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द कर देते हैं और सभी अदालतों में अपीलकर्ताओं की लागत के साथ ट्रायल जज के फैसले को बहाल करते हैं।

अपील की अनुमति दी गई

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री हनुमान प्रसाद आर जे एस द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।